an>

Title: Regarding problems faced by employees associated with Saakshar Bharat Mission in Jharkhand -laid.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): मैं सरकार का ध्यान साक्षर भारत मिशन योजना अंतर्गत लगे साक्षरता कर्मियों की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि देशभर में साक्षर भारत मिशन योजना अंतर्गत 5.5 लाख साक्षरकर्मी संविदा पर कार्यरत हैं। अकेले झारखण्ड में इनकी संख्या 50,000 से अधिक है। वर्ष 1999 से लेकर 2009 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत ये साक्षरता कर्मी स्वयं सेवक के पद पर निस्वार्थ भाव से असाक्षरों को पढ़ाने के साथ-साथ लगातार सामाजिक कार्य करते रहे हैं। वर्ष 2010 से साक्षर भारत मिशन के तहत पंचायत क्षेत्र के लोक शिक्षा केन्द्र में ये प्रेरक के पद पर काम कर रहे हैं। इसके एवज में इन्हें 67 रूपये दैनिक के हिसाब से 2000 रू0 मासिक मानदेय मिलता है। सरकार द्वारा चलाये जाने वाली विभिन्न योजनाएं और कार्य जैसे पल्स पोलियो, कुष्ठ उन्मूलन, पी0डी0एस0 सुपरवाइजर, मतदान कार्य, योजना बनाओं अभियान, मनरेगा कार्य, स्वच्छ भारत सर्वे, आर्थिक गणना, जन-धन खाता खुलवाना, अटल पेंशन योजना, स्कूल चलें अभियान के अलावा पारा शिक्षकों के हड़ताल की अवधि में विद्यालय में पठन-पाठन कार्य करना आदि कार्य सरकार द्वारा प्रेरकों से लिया जाता है, जिसे ये न्यूनतम वेतनमान में भी ईमानदारी पूर्वक असाक्षरों को पढ़ाने के साथ साथ कर रहे हैं। परन्तु सरकार ने 31 मार्च, 2018 के बाद साक्षर भारत मिशन को स्थगित कर दिया है, जिसके कारण सभी साक्षरताकर्मी बेरोजगार होकर भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं।

अतः सरकार से मांग है कि साक्षरता कर्मियों का सेवा विस्तार कर इन्हें नियमित किया जाये या सरकार के अन्य कार्यक्रमों में इन्हें समायोजित किया जाये तथा साक्षरता कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान करते हुए साक्षरता कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाये।